These objectives are in consonance with the objectives of Industrial Policy Resolution of 1956.

देश में आंत्रशोथ के कारण हुई मौतें

2341. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष देश भर में आंत्रशोथ जैसी जानलेवा बीमारियों से अनेक जानें गई है;

(ख) यदि हां, तो 31 जुलाई, 1995 तक राज्य-वार कितनी-कितनी जाने गई;

(ग) क्या केन्द्रीय स्वस्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इन जानलेवा बीमारियों से लोगों की जान बचाने तथा इनके रोकथाम व उपचार के लिए राज्यों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इस वर्ष नकद तथा औषधियों के रूप में राज्य वार कितनी-कितनी सहायता दी गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डा० सी० सिल्वेरा): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) शिशु जीवनरक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम जिसका उद्देश्य पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में अतिसारीय रोगों के कारण मृत्यु दर को कम करना है, के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर माताओं की बैठक का आयोजन करने के लिए नकद सहायता प्रदान की जाती है और 1995-96 के दौरान इस कार्यकलाप के लिए राज्यों को 2.51 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त 1995-96 के दौरान बच्चों में अतिसारीय निर्जलीकरण के रोगीयों का उपचार करने के लिए राज्यों को ओर्स के 5.46 करोड़ पैकेट आबंटित किए गए हैं। मलेरिया फैलने की घटनाओं की जांच पड़ताल करने और उपचारात्मक उपायों के बारे में परामर्श देने की लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है।

विवरण

1995 को दौरान केन्द्रीय स्वास्थय आसूचना ब्यूरों को यथासूचित हैजे और तीव्र अतिसार रोगों (जठरान्त्र शोथ समेत) के कारण मौतों की संख्या

(जून, 1995 तक)

क्रम सं०	राज्य	मौतों की संख्या
1.	2.	3.
1.	आन्ध्र प्रदेश	36
2.	अरूणाचल प्रदेश	अप्राप्त
3.	असम	अप्राप्त
4.	बिहार	अप्राप्त
5.	गोवा	14
6.	गुजरात	19
7.	हरियाणा	19
8.	हिमाचल प्रदेश	11
9.	जम्मू और कश्मीर	0
10.	कर्नाटक	62
11.	केरल	5
12.	मध्य प्रदेश	47
13.	महाराष्ट्र	31
14.	मणिपुर	

क्रम सं॰	राज्य	भौतों की संख्या
1	2.	3.
		अप्राप्त
15.	मेघालय	1
16.	मिजोरम	7
17.	नागालैंड	3
18.	उड़ीसा	46
19.	पंजाब	4
20.	राजस्थान	1
21.	सिक्किम	अप्राप्त
22.	त्रिपुरा	19
23.	तमिलनाडु	अप्राप्त
24.	उत्तर प्रदेश	अप्राप्त
25.	पश्चिम बंगाल	अप्राप्त
26.	अंडमान और निकोबार	1
27.	चंडीगढ़	अप्राप्त
28.	दादरा और नगर हवेली	2
29.	दमण और दीव	0
30.	दिल्ली	2
31.	लक्षद्वीप	8
32.	पांडिचेरी	8
	योग:	338

Production of heavy vehicles in the country

2342. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of heavy vehicles produced in the country during last three years;

(b) the details of public as well as private sector companies producing different kinds of heavy vehicles;

(c) whether there has been a steep rise in demand for heavy commercial vehicles; and

(d) if so, the details of steps taken by Government to meet the growing demand of heavy commercial vehicles?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) Number of heavy vehicles produced in the country during the last three years are:

1992-93	— 76,051
1993-94	— 65,975
1994-95	— 1,02,002

(b) Heavy Commercial Vehicles are produced by M/s. TELCO, Ashok Leyland and Hindustan Motors.

(c) The sales of Heavy Commercial Vehicles have increased from 67,981 in 1992-93 to 76,245 in 1993-94 and to 1,03,733 in 1994-95.

(d) The manufacture of heavy commercial vehicles has been delicensed